

कमजोर वर्ग के उत्थान हेतु भारत सरकार द्वारा संचालित¹ योजनाओं के लाभ के सन्दर्भ में एक अध्ययन

डा० कान्ता देवी
सहायक प्रोफेसर
पूजा कालेज ऑफ ऐजुकेशन, पिपली कुरुक्षेत्र

सारांश

वर्तमान युग में हर सरकार का विकास एक महत्वपूर्ण नारा है चुनाव से पहले हर राजनीतिक दल सत्ता में आने के लिए अपने घोषणा पत्र में सैंकड़ों विकास योजनाओं का वादा करता है। इसके साथ हर राजनीतिक दल का लक्ष्य कमजोर वर्ग होता है कमजोर वर्ग को लुभाने के लिए उनको विकास के बड़े-बड़े सपने दिखाए जाते हैं और हर सरकार अपनी पंचवर्षीय योजना में कमजोर वर्ग के उत्थान हेतु बहुत सारी योजनाएं किर्यान्वित की जाती हैं क्या इन योजनाओं का लाभ सम्बन्धित वर्ग को मिल पाता है इस शोध पत्र में यह जानने की कोशिश की गई है। शोध कार्य के लिए सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

1.0 प्रस्तावना:

आज 21वीं शताब्दी में जब दुनिया के नये-नये स्वरूप नयी प्रतिस्पर्धा विकास के आधुनिक तकनीक युक्त नामों, बड़े-बड़े विकासकारी कार्यों और बहुत अधिक लम्बे चौड़े विचार-विमर्श एवं चर्चा-परिचर्चा हो रहे हो तब इस तरह के वातावरण में यह विमर्श और महत्वपूर्ण हो जाता है। 1993 के अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले अमेरिकी अर्थशास्त्री रॉबर्ट विलियम फॉसेज ने अपने एक अध्ययन के दौरान यह पाया कि दास प्रथा के कारण ही अमेरिका को बाजारवादी व्यवस्था का नेतृत्वकर्ता बनने का अवसर मिला और इस प्रक्रिया में पुरी की पुरी निपो नस्ल गायब हो गई अनुमान लगाया जाए कि दुनिया के सभी भागों में जहां इस तरह का विकास पहुँचा होगा वहाँ स्थिति क्या रही होगी। सवाल यह उठता है कि क्या इसी तरह के निष्कर्ष भारत के बारे में भी निकाले जा सकते हैं। क्या भारत में जो विकास हुआ वह कमजोर वर्ग को समाज की मुख्यधारा में ला सका या वांचितों की जमात का एक हिस्सा बनकर सिर्फ गणनाओं तक ही सीमट कर रह गया।

भारत की आजादी की लड़ाई में वंचित वर्ग की निर्णयिक भूमिका रही लेकिन भागीदारी को उजागर ही नहीं होने दिया। इसकी झलक हमें भारतीय इतिहास लेखन में मिल सकती है।

पहली पंचवर्षीय योजना में कमज़ोर वर्ग के विकास के लिए कोई महत्वपूर्ण तथा विशेष भूमिका का निर्वहन नहीं किया गया। कुछ अनिवार्य क्षेत्रों जैसे शिक्षा कल्याणकारी योजनाओं आदि को इसमें शामिल कर लिया गया था। लेकिन इसके बावजुद विकास की गति बहुत धीमी थी। चौथी पंचवर्षीय योजना तक आते-आते इटेसिव डेवलपमेंट एरियाज जहाँ बड़े पैमाने पर वंचित वर्ग रहता हो उसमें आर्थिक सुधार के लिए 489 कमज़ोर वर्ग विकास खण्ड बनाए गए। इन विकास खण्डों को 10 से 15 वर्ष कार्य करना था। प्रति ब्लॉक के लिए 10 से 15 वर्ष तक कार्य करना था। प्रति ब्लॉक के लिए 10 लाख रुपए प्रति पांच वर्ष के लिए आंबटिट थे इस योजना के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 75 करोड़ रुपये खर्च किए गये। गांधी जी ने कहा था जब तक अन्तिम छोर तक बैठे व्यक्ति का विकास नहीं होता तब तक विकास को पूर्ण नहीं माना जा सकता। भारत की कुल आबादी में लगभग चौथा हिस्सा वंचित वर्ग का है। भारत सरकार ने पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर अब तक इस वर्ग के लिए बहुत सारी योजनाएं इनके विकास के लिए चलाई हैं। क्या इनको इसका लाभ मिल पाया है?

2.0 साहित्य समीक्षा

विकास एक बहुआयामी व जटिल अवधारणा है। वस्तुतः विकास एक मानसिक स्थिति है, भौतिक उन्नति है। कमज़ोर वर्ग के उत्थान के लिए सामाजिक राजनैतिक व आर्थिक विकास जिसमें शिक्षा स्वास्थ्य, आवास, रोजगार, पेयजल, आदि को सम्मिलित किया जाता है अगर इतिहास पर नज़र डाले तो इनकी स्थिति अच्छी थी देश के करीब 15 फीसदी भू-क्षेत्र में विभिन्न परिस्थितियों में इस वर्ग की दशा काफी शोचनीय है। (अरविन्द कुमार सिंह) पृ. 12 योजना 2014

वर्ष 2014 में योजना पत्रिका में वंचित वर्ग को मिलने वाली योजनाओं के लाभ में अध्ययन किया गया तो यह पाया गया कि आजादी के बाद से ही अंतिम व्यक्ति देश की योजनाओं में तो रहा लेकिन वह हाशिए पर धकेला गया।

3.0 शोध विधि:

इस शोध कार्य के लिए कुरुक्षेत्र शहर की चार ऐसी बस्तियों में वंचित वर्ग के व्यक्तियों का चुनाव दैव निर्दशन विधि द्वारा किया गया। प्रश्नावली के माध्यम से इनके लिए चलाई जा रही योजनाओं से मिलने वाले लाभ पर प्रश्न पुछे गये।

4.0 शोध प्रश्न:

- शोध का प्रमुख उद्देश्य योजनाओं के प्रति जागरूकता है यह जानना है।
 - वह इन योजनाओं के बारे में जानकारी कहा से हासिल करती है।
 - कितने लोगों को इसका फायदा मिला है।
1. आप कितने पढ़े लिखे हैं?
 2. आपको सरकार द्वारा चलाई गई विकास योजनाओं की कितनी जानकारी है?
 3. आपको इस योजना के बारे में कहां से व किस माध्यम से पता लगा?
 4. आपके घर में सूचना के कौन-कौन से साधन हैं?
 5. आपके लिए चलाई योजना का लाभ क्या आपको आसानी से मिल जाता है?
 6. क्या इन योजनाओं को आप अपने विकास में सहायक मानते हैं?
 7. इन योजनाओं का लाभ उठाने में आपको क्या दिक्कतें आती हैं?
 8. इन योजनाओं से आपके जीवन स्तर में क्या बदलावा आया है?
 9. सरकार द्वारा इन योजनाओं को आप तक पहुंचाने में कोई मदद होती है?
 10. ये योजनाओं आपक पिछड़ापन दूर करने में कितनी सहायक सिद्ध हुई हैं?

5.0 परिणाम एवं परिचर्चा

तालिका 1
योजना की जानकारी

जवाब	पुरुष	स्त्री
हाँ	47%	47%
नहीं	18%	18%
थोड़ी बहुत	27%	27%
कह नहीं सकते	8%	8%

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि कमज़ोर वर्ग में योजना की जानकारी के सन्दर्भ में यह उत्तर सामने आया है कि 47 प्रतिशत पुरुष और 47 प्रतिशत स्त्रीयों ने हाँ में

जवाब दिया और 18 प्रतिशत ने नहीं कहा, 27 प्रतिशत ने कहा की थोड़ी बहुत जानकारी है। 8 प्रतिशत का जवाब कह नहीं सकते रहा।

तालिका 2

योजना की जानकारी का माध्यम

माध्यम	पुरुष	स्त्री
समाचार-पत्र	25%	28%
रेडियो	22%	20%
टेलीविजन	47%	43%
कह नहीं सकते	6%	9%

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि योजना की जानकारी का माध्यम के बारे में बात की गई तो 25 प्रतिशत पुरुष और 28 प्रतिशत स्त्री ने समाचार-पत्र को माध्यम बताया। 22 प्रतिशत पुरुष और 20 प्रतिशत स्त्री ने रेडियो को माध्यम बताया। 47 प्रतिशत पुरुष और 43 प्रतिशत स्त्री ने टेलीविजन को माध्यम बताया। 6 प्रतिशत पुरुष और 9 प्रतिशत स्त्री ने कह नहीं सकते को माध्यम बताया।

तालिका 3

योजना का लाभ कितने प्रतिशत लोगों को मिला

जवाब	पुरुष	स्त्री
हाँ	45%	45%
नहीं	20%	20%
थोड़ी बहुत	25%	25%
पता नहीं	10%	10%

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है योजनाओं का लाभ 45 प्रतिशत पुरुष और 45 प्रतिशत स्त्री ने हाँ में और नहीं में 20 प्रतिशत और थोड़ी बहुत ने 25 प्रतिशत में और पता नहीं ने 10 प्रतिशत में जवाब दिया।

तालिका 4 योजना का लाभ न उठा पाने के कारण

जवाब	पुरुष	स्त्री
जानकारी की कमी	20%	18%
मुश्किल प्रक्रिया	25%	22%

भ्रष्टाचार	50%	53%
अन्य	5%	7%

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि योजना का लाभ न उठा पाने का कारण में जानकारी की कमी का कारण 20 प्रतिशत पुरुष और 18 प्रतिशत स्त्री, मुश्किल प्रक्रिया 25 प्रतिशत पुरुष, 22 प्रतिशत स्त्री, भ्रष्टाचार 50 प्रतिशत पुरुष, 53 प्रतिशत स्त्री, अन्य 5 प्रतिशत पुरुष, 7 प्रतिशत पुरुष मानते हैं।

6.0 निष्कर्ष

शोध से पता चलता है कि पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीमों की पहुंच व इसका लाभ उठाने वाले लोगों की सम्बंधी सीमित है।

- शोध से पता चलता है कि 47 प्रतिशत लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही उत्थान स्कीमों के बारे में पता है जबकि 27 प्रतिशत लोगों को इस की थोड़ी बहुत जानकारी है।
- टेलीविजन को शासक्त माध्यम के रूप में देखा जा सकता है। 43 प्रतिशत लोगों को टेलीविजन से जानकारी प्राप्त होती है। दुसरे नम्बर पर क्रमशः रेडियों को जाना जाता है।
- शोध से पता चलता है कि केवल 49 प्रतिशत लोग ही इन स्कीमों का फायदा उठा सकते हैं 27 प्रतिशत लोग इससे कोई फायदा नहीं उठा सकते। 19 प्रतिशत लोग इसका थोड़ा बहुत फायदा उठा सकते हैं।
- प्रस्तुत शोध के लिए यह भी जाना गया कि लोगों को इस जानकारी का लाभ उठाने में किन-किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता हो 53 प्रतिशत् लोगों ने इसका मुख्य कारण भ्रष्टाचार को माना है। 22 प्रतिशत् मुश्किल प्रक्रिया को भी कारण मानते हैं। 18 प्रतिशत लोगों को जानकारी की कमी रहती है कि किस तरह से लाभ उठाया जाए।

7.0 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. दीपिका कच्छल, ऋतेश पाठक, 'योजना' (केन्द्रिय बजट मार्च 2017) सहायक निदेशक (प्रसार एवं विज्ञापन) सूचना भावना सी जो परिसर लोधी रोड़, नई दिल्ली
2. दीपिका कच्छल, ललिता खुराणा, जून 2017 प्रकाशन विभाग, सूचना औष्ठ्र प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली।
3. सचदेव, डी.आर., भारत में समाज कल्याण, किताब महल प्रकाशन, दिल्ली
4. श्रीवास्तव, डी.एन., अनुसंधान विधियां, साहित्य प्रकाशन, आगरा

5. शर्मा, राधे श्याम, विकासात्मक संचार, हरियाणा साहित्य अकादमी, पंचकूला
6. गंगा सहाय मीणा: आदिवासी साहित्य और समाज, 2014